at the Centre, the services of Shri Mahishi had been offered for posting elesewhere. *So* long as alternative posting could not be made. Shri Mahishi was on compulsory wait to avoid any hardship to him. in regard to his salary etc. Shri Mahishi has since been appointed as Exective Director,. TRIFED under the Ministry of Welfare and he has joined this post. Presently, there" are two other IAS officers namely S/Shri K. Kipgen,, IAS (MT:65) and V.S. Jafa, IAS (AM:65), who are on compulsory wait and efforts are being made to provide them alternate posting. Information about being made to provide them alternate posting. Information about the officers on compulsory wait in the State. Governments, is not ' centrally maintained. As a matter of practice, the cases of officers on compulsory wait, are considered on priority basis by offering them to appropriate Ministeries/ Departments.

**शिकायत कक्ष**

2770. **श्री राम नरेश यादवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में शिकायत कक्ष स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायत कक्षों द्वारा जनता की कठिनाईयों का निदान शीघ्र किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले 6 महीनों के दौरान प्रत्येक कार्यालय को कितनी शिकायतें मिली, उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया और उनमें से कितनी शिकायतें अभी भी लम्बित हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):** (क) और (ख) भारत सरकार ने मंत्रालयों/विभागों तथा इनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन वाले मुख्य संगठनों में शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करने के लिये अनुदेश जारी किये है। इन कक्षों के मुखिया उप सचिव/निदेशक के कम के औहदे का अधिकारी नहीं होता है जिसे प्रायः शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है। वह पूरे संगठन के शिकायत निवारण के कार्य की देख-रेख करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने लोक शिकायतों के तत्परता और सहानुभूतिपूर्वक निवारण को मद्दे नजर रखते हुये सरकार के कार्यालयों के कार्य संचालन को सुदृढ़ करने के लिये अनुदेश जारी किये हैं।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून, 1992 तक की 6 माह की अवधि के दौरान 5,70,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 4,72,000 शिकायतें निपटाई गई थीं और लगभग 98,000 शिकायतें लम्बित हैं।

2771. *[Transferred to 18th December, 1992]*

**Unaccounted Assets of Senior IAS Officers**

2772. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during 1990, raids were conducted on few senior IAS officers based in Karnataka and large Un-accounted . assets were discovered and seized thereafter;

(b) if so, the details of the officers connected indicating the assets discovered;

(c) what follow up and corrective action was taken in the matter of the above cases individually; and

(d) whether any of the guilty officers is still serving in the State of elsewhere if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.